

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1182
06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओडिशा में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं की कमी

†1182. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ओडिशा के बरगढ़ जिला अस्पताल में न केवल बरगढ़ बल्कि आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में मरीज आते हैं और वहां पर्याप्त सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं नहीं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बरगढ़ जिला अस्पताल को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और ट्रॉमा केयर जैसे उन्नत विभागों से युक्त सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नयन करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को ओडिशा राज्य सरकार से बरगढ़ जिले में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या उस पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति, इसकी मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पश्चिमी ओडिशा में जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं और चिकित्सा पेशेवरों की कमी को देखते हुए बरगढ़ में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त राज्य के बरगढ़ और आसपास के जिलों में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): बरगढ़ जिले सहित ओडिशा राज्य के स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28I%20nfrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%209.pdf

एचडीआई 2022-23 के अनुसार, ओडिशा के बरगढ़ जिले से सटे जिलों, बालांगीर और संबलपुर प्रत्येक में एक-एक मेडिकल कॉलेज है।

इसके अलावा, ओडिशा राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, बरगढ़ जिला अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 700-800 रोगी ओपीडी में आते हैं, जिसका प्रबंधन लगभग 35 चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ई-संजीवनी के माध्यम से विशिष्ट परिचर्या के साथ सुपर-स्पेशलिस्ट परामर्श किया जाता है। बरगढ़ जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला कैंसर विंग पहले से ही संचालनरत है और बरगढ़ के जिला अस्पताल में डे केयर कीमोथैरेपी भी की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने हेतु दी गई स्वीकृतियों का विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

www.nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=45&lid=58

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 604 भवन रहित एएएम (उप-केंद्रों - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र), 140 शहरी एएएम (यू-एचडब्ल्यूसी), 197 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 30 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 28 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढीकरण के लिए ओडिशा राज्य को योजना अवधि (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के लिए 1411.38 करोड़ रुपये की राशि हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत, बरगढ़ जिले को पांच वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-2026) के लिए 116.46 करोड़ रुपये की राशि से एक (01) एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल), एक (01) क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी), बारह (12) ब्लॉक जन

स्वास्थ्य इकाई (बीपीएचयू) और ग्रामीण क्षेत्रों में चौबीस (24) उप स्वास्थ्य केंद्रों (एससी) के निर्माण/सुदृढीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई है।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** का उद्देश्य देश में किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाकेंद्रों को बढ़ाना है। इस योजना के तहत ओडिशा राज्य के लिए भुवनेश्वर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और बहरामपुर, बुरला और कटक में तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन को मंजूरी दी गई है।
- केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, **'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना'** के लिए उन क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। ओडिशा राज्य में बालासोर, बारीपाड़ा, बालांगीर, कोरापुट, पुरी, जाजपुर और कालाहांडी जिलों में 7 चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई थी।
